क्या वाकई दो महीने में नीलम पुल की मरम्मत पूरी हो पाएगी ?

कबाड़ी का नाम जगदीश से 'असलम' करने की साजिश नाकाम

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: अग्निकांड का शिकार हुए नीलम पुल की मरम्मत का काम शुरू हो गया है और करीब दो महीने में इसे पूरा करने की डेडलाइन नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) ने तय की है। इस तरह अगले साल फरवरी में जाकर इस पुल पर ठीक तरीके से ट्रैफिक शुरू हो पाएगा। 22 अक्टूबर को इस पुल के नीचे कबाड़ में आग लग गई थी, उसके बाद पुल को बंद कर दिया गया था। कुछ दिनों बाद पुल के एक हिस्से को खोला गया। लेकिन सारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था लड़खड़ा गई है।

काम शुरू होने के बावजूद यह संशय बना हुआ है कि क्या वाकई दो महीने में मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। दरअसल, ऐसे काम में एमसीएफ के ठेकेदार बीच में काम छोड़ देते हैं या उसे लंबा कर देते हैं, जिससे उसकी लागत पर सौदेबाजी की जा सके। अगर इसमें ठेकेदार को एमसीएफ के अफसरों को कमीशन नहीं देना पड़ा तो वाकई यह काम दो महीने में खत्म हो जाएगा लेकिन अगर ठेकेदार को कमीशन देना पड़ा तो वह इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़वा सकता है।

यह काम इमरजेंसी में सीधे कोटेशन के जरिए करवाया जा रहा है तो इसका भुगतान भी फौरन होगा। एमसीएफ में किसी भी भुगतान को 'कमीशन नामक प्रक्रिया' से गुजरना पड़ता है। चूंकि ठेकेदार को एमसीएफ में पहला काम मिला है, इसलिए सारा पुल का काम समय पर पूरा होने का सारा दारोमदार 'कमीशन और सेटिंग' पर निर्भर करेगा।

दिल्ली की कंपनी को ठेका

एमसीएफ ने पुल के एक हिस्से की मरम्मत का ठेका दिल्ली की कंपनी एसएसए टेक्नो कंस्ट्रक्शन कंपनी को 35 लाख रुपये में दिया गया है। इस ठेके का रिजर्व रेट पहले 25 लाख रुपये एमसीएफ ने रखा था लेकिन जब कोई ठेकेदार इसे लेने का राजी नहीं हुआ। इसके बाद एमसीएफ ने इसमें दस लाख रुपये और बढ़ा दिए। कंपनी ने पुल के नीचे बाकायदा हवन करके काम शुरू कर दिया है। हालांकि गुरुवार को इस संवाददाता ने जब मौका मुआयना किया तो वहां काम शुरू करने के नाम पर क्षतिग्रस्त पिलर के चारों तरफ मिट्टी खोदी गई थी और कुल आठ कर्मचारी मौके पर काम कर रहे थे।

कंपनी के साइट इंजीनियर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि हमारी कोशिश है कि डेढ़ महीने में इस काम को खत्म कर लिया जाए। जल्द ही कंपनी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देगी, तब जाकर काम और तेज हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले पिलर की मरम्मत की जाएगी और फिर सपोर्ट सिस्टम पिलर के चारों तरफ खड़ा किया जाएगा। सपोर्ट सिस्टम से ही पुल को मजबूती मिलेगी।

अफसरों की बदमाशी

नीलम पुल के नीचे आग लगने की घटना की जांच आज भी बंद नहीं हुई है। लेकिन कमिश्नर यश गर्ग अभी तक इस घटना के जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय नहीं कर सके हैं। इस गंभीर घटना के बाद एमसीएफ कमिश्नर से फौरन कार्रवाई की दरकार थी लेकिन वह इस मामले में कुंडली मार कर बैठे हुए हैं।

आग लगने के फौरन बाद एमसीएफ की ओर से जगदीश नामक कबाड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कबाड़ी जगदीश उसी वक्त फरार हो गया था। लेकिन नगर निगम के कुछ अफसरों ने कबाड़ी के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया के एक वर्ग को बता दिया कि यह कबाड़ किसी असलम नामक शख्स का था। यानी इसके पीछे चाल यह चली गई कि अगर असलम पर मीडिया ने फोकस कर दिया तो भाजपाई पार्षद और नेता इसे दूसरा रंग देने और नीलम पुल की आग को साम्प्रदायिक बना देने में जरा भी देर नहीं लगायेंगे। एक तरह से असलम का नाम साबित होने और भाजपा द्वारा इसे दूसरा रंग देने से वो अफसर बच जाएंगे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। जो नीलम ही नहीं, बाटा और बडखल पुल के नीचे से अवैध कमाई करते हैं। लेकिन पुलिस ने एफआईआर में वही लिखा जो उसे सबसे पहले एमसीएफ ने बताया था। जब तक पुलिस अपनी एफआईआर में जगदीश को असलम नहीं बनाएगी तब तक भाजपाई पार्षदों और भाजपाई अफसरों की दाल नहीं गलने वाली। मजेदार बात यह है कि निगम के अधिकारी ठेकेदार जगदीश के नाम से पांच हजार का चालान भी काट चुके हैं।

देखना यह है कि एमसीएफ कमिश्नर इस गंभीर घटना की जांच कब फाइनल कराते हैं और किन-किन अफसरों पर कार्रवाई करते हैं या फिर बिना कार्रवाई के यहां से विदा ले लेंगे।

नया अस्पताल बना नहीं सकते, बीके का नाम बदलकर क्या तीर मार लेंगे खट्टर

फरीदाबाद की शानदार विरासत के भाजपाईकरण की चिन्ता शहर को नहीं है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: शहर के एकमात्र सिविल अस्पताल का नाम ऐतिहासिक हस्ती और भारत रत्न बादशाह खान (बीके) का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम करने पर इस शहर का कद छोटा हो गया है। अस्पताल के सिविल सर्जन को 3 दिसम्बर को एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इच्छा है कि बीके अस्पताल का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सिविल अस्पताल कर दिया जाए। इस खबर को फैले 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन शहर के किसी भी जागरूक नागरिक संगठन या राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। हरियाणा में और देश में पिछले छह साल से भाजपा का शासनकाल है लेकिन देश में कोई नया अस्पताल खोलने या शहर बसाने की बजाय पुराने का नाम बदलकर अपनी बड़ी उपलब्धि साबित करना ही उसका काम रह गया है। 1951 में पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बीके अस्पताल को फरीदाबाद वालों को समर्पित किया और खुद इसका नाम बादशाह खान के नाम पर रखा था।

फरीदाबाद को चाहिए दो और अस्पताल

बीके अस्पताल का नाम बदलने की बजाय फरीदाबाद से चुने गए किसी भी विधायक या सांसद ने यह बात नहीं रखी कि फरीदाबाद में कम से कम दो और अस्पताल खोले जाने चाहिए। फरीदाबाद की लाखों की आबादी का सारा दारोमदार अकेले इसी अस्पताल पर है। जबकि नहर पार की शहरी आबादी और खासकर ग्रामीण इलाके की आबादी के लिए अलग से सरकारी अस्पताल की सख्त जरूरत है। प्रॉपर्टी के रेट बढ़वाने के लिए मझावली में यमुना पर पुल तो बनाने का ड्राम किया जा सकता है लेकिन अस्पताल का वादा केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूर्जर के घोषणा पत्र या कथित संकल्प पत्र में कभी नहीं था। बल्लभगढ़ में एक अदद सरकारी अस्पताल की सख्त जरूरत है लेकिन यह मंत्री मूलचंद शर्मा के चुनावी वादे में कभी शामिल नहीं था। बडखल की विधायक सीमा त्रिखा ने अपने ही इलाके में छोटी डिस्पेंसरी का जाल बिछाने के बारे में मुख्यमंत्री से कभी बात नहीं की। मतदाताओं की सेहत से इन सत्ताधीशों को कोई मतलब नहीं है। आम जनता, महिलाओं, बच्चों की सेहत किसी भी चुनाव में मुद्दा नहीं बनता और तमाम मूर्ख मतदाता इन मुद्दों पर सोचने की बजाय धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर मतदान करते हैं।

खट्टर की चाल

मनोहर लाल खट्टर को शुरू से ही इस अस्पताल का नाम खटकता रहा है। 2014 में उन्होंने हरियाणा की सत्ता संभालते ही सबसे पहले इस अस्पताल का नाम बीके अस्पताल से सिविल अस्पताल फरीदाबाद कराया। लेकिन यह सिर्फ प्रयोग भर था। खट्टर यह देखना चाहते थे कि बीके अस्पताल का नाम बदलने से शहर में कोई प्रतिक्रिया होती है या नहीं। ...खट्टर का अनुमान सही था। शहर सोया रहा। अस्पताल का नाम बदल दिया गया। खट्टर ने लंबी प्रतीक्षा की कि शायद कहीं से विरोध की लहर उठे। जब कहीं से कोई विरोध की लहर नहीं उठी तो इस बार इसका नाम अटल के नाम पर कर दिया गया। खट्टर को मालूम है कि अटल के नाम पर वैसे भी कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन अपने एजेंडे पर भाजपा इसी तरह चलती है और काम करती है।

बादशाह खान इस शहर में आते रहे हैं। कई पंजाबी नेताओं से उनके संबंध रहे हैं। उनके द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार संगठन से लोग जुड़े रहे हैं। यह संगठन दिल्ली और देशों के तमाम हिस्सों में और पाकिस्तान के फ्रंटियर इलाकों में आज भी कायम है। पूर्व मंत्री एसी चौधरी तो बादशाह खान को नजदीक से जानते हैं और इस समय भाजपा में हैं। वो विरोध का एक पत्र तक अपनी पार्टी को नहीं लिख सके। शहर के वयोवृद्ध पत्रकार अमरनाथ बागी का संबंध भी बादशाह खान से रहा है। हैरान है कि वो भी चुप्पी साध गए। इसी तरह शहर के तमाम परिवार हैं जो बादशाह खान या उनके संगठनों से जुड़े रहे हैं। लेकिन किसी को जरा भी ऐतराज नहीं हुआ।

विरोध में चंद लोग

शहर से सिर्फ समाजसेवी विनोद मलिक ने आवाज उठाई है। उन्होंने इस संबंध में पोस्ट लिखकर बीके अस्पताल का नाम बदले जाने का खुला विरोध किया है। उनका कहना है कि यह फरीदाबाद का अपमान है। बता दें कि विनोद मलिक के पिता जुगल किशोर मलिक खुद स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी रहे हैं। विनोद मलिक द्वारा फेसबुक पोस्ट पर दर्ज कराए गए विरोध का शहर के कुछ और लोगों ने समर्थन किया है लेकिन शहर की बड़ी आबादी खामोश है। शहर में ऐसा कोई नागरिक संगठन भी नहीं है जो इस तरह की पहल करता रहा हो। फरीदाबाद पाकिस्तान से आये हुए लोगों से आबाद है। लेकिन उनकी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपनी बोलचाल, अपनी विरासत संभाल कर रखने की तमीज नहीं है। ऐसे में विनोद मलिक जैसों की आवाज नक्कारखाने में तूती की तरह ही कही जा सकती है।

भारत रत्न बादशाह खान का इतिहास पढ़ो

फरीदाबाद के नेताओं और खासकर युवा पीढ़ी को भारत रत्न बादशाह खान का इतिहास पढ़ना चाहिए। भारत की आजादी की लड़ाई में शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी के साथ खड़े होने वाले बादशाह खान को इस शहर को बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। बादशाह खान कई नामों से मशहूर हैं। उनका एक नाम बाचा खान था। दरअसल, उनके दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान को पश्तो में बाचा खान कहा जाता है। पाकिस्तान में बाचा खान ज्यादा मशहूर है।

'बाचा खान' पश्तो लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसा के रास्ते से लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी से उनकी करीबी दोस्ती थी लेकिन उन्होंने भारत के बंटवारे का विरोध किया था। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारत के बंटवारे पर अड़ी, तब बाचा खान ने इसका सख्त विरोध किया। जब कांग्रेस ने बंटवारे के समझौते को 'खुदाई खिदमतगार' के लीडरों से सलाह किए बिना स्वीकार कर लिया, तो बाचा खान बेहद दुखी हो गए। उन्होंने गांधी और नेहरू से कहा, आपने हमें भेड़ियों की तरफ फेंक दिया है।

1929 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार (अल्लाह के सेवक) मूवमेंट शुरू किया। इससे ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उन्हें और उनके समर्थकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

बंटवारे के बाद बाचा खान ने पाकिस्तान में आजाद पश्तूनिश्तान की मांग बुलंद की। लेकिन पाकिस्तानी सरकार हमेशा उनसे खतरा महसूस करती रही। पहले 1948, फिर 1954 और फिर 1956 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1960 और 70 के दशक का भी काफी समय उन्होंने या तो जेल में बिताया या निर्वासन में। 1988 में पेशावर में हाउस अरेस्ट होने के दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी इच्छा के मुताबिक जलालाबाद, अफगानिस्तान स्थित उनके घर के पास उन्हें दफनाया गया। हालांकि इन चंद लाइनों में बादशाह खान का इतिहास नहीं बताया जा सकता। उनकी कहानी लम्बी है।

यह अटल बिहारी का भी अपमान है

मनोहर लाल खट्टर को यदि अटल बिहारी वाजपेयी से वास्तव में ही प्यार है, उनकी इज्जत करते हैं और उनका अपना रहनुमा व देश का एक बड़ा नेता मानते हैं तो उनके नाम पर कोई नया संसाधन बनाते। या कोई बड़ा अस्पताल, बड़ा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज या आईआईटी सरीखा कोई संस्थान हो सकता था।

स्व० वाजपेयी के नाम यह पुराना जर्जर व पूरी तरह से बदनाम हो चुका अस्पताल समर्पित करके खट्टर ने उनकी बहुत बड़ी तौहीन की है। यह ठीक उसी तरह घटिया कृत्य है, जैसे किसी भी उतरन, यानी उतरी हुई पोशाक किसी दूसरे को पहना दी जाये।

अनिल विज प्राइवेट अस्पताल की शरण में, जनता क्या मरने के लिए है...

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इस बार कोविड 19 ने अपने चंगुल में ले लिया है। हम लोगों की उनसे पूरी सहानुभूति है और उनके जल्दी स्वस्थ्य होने की कामना करते हैं। लेकिन मंत्री के इस व्यवहार पर सवाल तो बनता ही है। जब उन्हें दस दिन पहले कोरोना हुआ तो वो अम्बाला के सिविल अस्पताल में भर्ती हो गए थे। तबियत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया।

इसके बाद मीडिया के एक वर्ग ने चमचागीरी करते हुए खबरें चलाईं कि अनिल विज कितने महान हैं कि प्राइवेट की बजाय सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। विज ने खुद बड़ी ही निर्लज्जता से इन खबरों को ट्वीट करके बताया है कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए मीडिया उनका गुणगान कर रहा है। फरीदाबाद में ब्राह्मणों की एक संस्था ने अनिल विज का गुणगान करते हुए हवन तक करा डाला।

चमचागीरी वाली इन खबरों को अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि मंत्री विज की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें फौरन गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब वो सारे चमचे पत्रकार और हवन करने वाले गायब हैं। यहां तक कि उनमें से कोई विज का हालचाल बताने तक तैयार नहीं है। बहरहाल, विज की तबियत स्थिर है। लेकिन मेदांता के डॉक्टरों ने और कोई जानकारी देने से इन्कार कर दिया है।

मजदूर मोर्चा के पाठकों को याद होगा कि कुछ महीने पहले बाथरूम में अनिल विज फिसल गए थे और उनके टांग की एक हड्डी टूट गई थी। उस समय अनिल विज पंजाब के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब फिर से उन्हें प्राइवेट अस्पताल की शरण में जाना पड़ा है। उन्हें पता है कि वे अगर हरियाणा सरकार के अस्पतालों में भर्ती हुए तो बीमारी और बढ़ जाएगी। लेकिन इन नेताओं और मंत्रियों ने गरीब जनता को इन्हीं सरकारी अस्पतालों के सहारे छोड़ दिया है। जहां न टेस्टिंग की ठीक से सुविधा है और न इलाज की। अगर सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर होती तो अनिल विज और खट्टर दोनों अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराते ही क्यों। सरकारी अस्पतालों की बदतर हालत के बावजूद जनता जागने को तैयार नहीं है।

विदित है कि विज बीते छह साल से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री चले आ रहे हैं। अस्पतालों की खस्ता हालत को लेकर विज ने लफ्फाजी, बयानबाजी व छापेमारी की नाटकबाजी के अलावा एक तिनका तक नहीं तोड़ा। इसके बावजूद वो आये दिन स्वास्थ्य सेवाओं में किये गये तथाकथित उल्लेखनीय सुधारों का बखान करते नहीं अघाते। कुदरत ने उन्हें बीते एक साल में दो बार अपने विभाग की उल्लेखनीय सेवाओं का तुजुर्बा करने का बेहतरीन अवसर प्रदान किया; परन्तु दोनों बार उन्होंने अपने विभाग को एकदम नाकारा पाकर प्राईवेट अस्पतालों की शरण में जाना पड़ा। यदि अनिल विज में कोई शर्मो-हया बाकी है तो उन्हें अपने इस पद से तुरन्त इस्तीफा देते हुए यह घोषित कर देना चाहिए कि उनकी सरकार के बस का नहीं है स्वास्थ्य विभाग चलाना।